

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 280
02 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में मत्स्यपालन क्षेत्र

280. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

श्री ससिकांत सेंथिल:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) सरकार द्वारा तमिलनाडु में मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार और योजना-वार कुल कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;
- (ग) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में शामिल परियोजनाओं और लाभार्थियों का कोई रिकॉर्ड है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या तमिलनाडु सरकार द्वारा मछली पकड़ने के नए बंदरगाहों, शीतागार अवसंरचना या जलीय कृषि परियोजनाओं के लिए प्रस्तुत कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उनकी मंजूरी के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
- (ङ) क्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार द्वारा फोरशोर एस्टेट, नोचिकुप्पम और तिरुवनमियूर में मछली पकड़ने के बंदरगाहों के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है;
- (च) दक्षिण चेन्नई में परियोजनाओं के लिए अब तक स्वीकृत या जारी की गई कुल राशि कितनी है; और
- (छ) क्या सरकार का बार-बार बाढ़ और चक्रवात से होने वाले नुकसान को देखते हुए, तमिलनाडु में शहरी तटीय आजीविका संबंधी अवसंरचना के लिए सहायता राशि बढ़ाने का विचार है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) : मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार वर्तमान में तमिलनाडु राज्य सहित देश में मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निम्नलिखित चार योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है:

- (i) फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 7,522.48 करोड़ रुपए के फंड के साथ कार्यान्वित किया गया है।
- (ii) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) को वित्तीय वर्ष 2020-21 से 20,750 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया गया है।
- (iii) प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) को वित्तीय वर्ष 2024-25 से PMMSY के तहत उप-योजना के रूप में 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ कार्यान्वित किया गया है।
- (iv) मछुआरों और मत्स्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) 2019 से कार्यान्वित किया गया।

मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने विगत 3 वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान PMMSY के तहत 101.09 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर के साथ 321.48 करोड़ रुपए की कुल लागत पर तमिलनाडु सरकार के 61 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने FIDF के तहत 289.65 करोड़ की कुल लागत से अन्य 33 फिशरीस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने सितंबर, 2024 में प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) के तहत एक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) लॉन्च किया है। PM-MKSSY का कार्यान्वयन वित्त वर्ष 2024-25 से शुरू हो गया है और अब तक तमिलनाडु राज्य के 1.51 लाख से अधिक लोगों ने NFDP पर पंजीकरण कराया है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम के तहत, तमिलनाडु के मछुआरों और मत्स्य किसानों को 2,56,437 KCC कार्ड स्वीकृत किए गए हैं। PMMSY, FIDF और PM-MKSSY के तहत अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों का योजना-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध-1 में प्रस्तुत किया गया है।

(ग): तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लाभार्थी और गैर-लाभार्थी-वार डेटा को नियमित रूप से PMMSY के MIS पोर्टल में अपडेट किया जा रहा है और तमिलनाडु के जिले-वार लाभार्थियों का विवरण भी राज्य में मॉटेन किया जाता है।

(घ) और (ङ) : तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) के तहत फिश लैंडिंग सेंटर्स के निर्माण/उन्नयन के लिए 38 नए फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। तमिलनाडु ने यह भी सूचित किया है कि FIDF के तहत तिरुवल्लूर जिले के नोचिकुप्पम में 6.32 करोड़ रुपए की लागत से फिश लैंडिंग सेंटर का परियोजना प्रस्ताव भी प्रस्तावित किया गया है। तमिलनाडु सरकार को FIDF पोर्टल पर प्रस्तावों को पूर्ण रूप में अपलोड करने की सलाह दी गई है।

(च): तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि लूप रोड फिश मारकेट नोचिकुप्पम में बनाया गया है, जो मरीना इलाके में एक मुख्य तटीय आजीविका केंद्र है, जो पारंपरिक मत्स्यन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में काम करता है। यह भी सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड [नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड (NFDB)] ने नीलांकरई में फिश मारकेट के निर्माण के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(छ): मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने विगत तीन वर्षों में PMMSY और FIDF के तहत 611.13 करोड़ रुपए के 94 फिशरीस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य में 32 करोड़ रुपए की कुल लागत से 16 मौजूदा तटीय मछुआरों के गांवों को भी क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज (CRCFVs) के रूप में विकसित करने के लिए लिया गया है। CRCFVs में अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर-सामुदायिक हॉल, चक्रवात / सुनामी शेल्टर, आपदा प्रतिरोधी मकान, रोड़ कनेक्टिविटी, लैंडस्केपिंग और ग्रीन बेल्ट विकास इत्यादि का निर्माण शामिल है। योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदत्त फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग सेंटर तटीय मछुआरा समुदायों को बाढ़, चक्रवात इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने के लिए आश्रय के रूप में भी कार्य करते हैं। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार तमिलनाडु सरकार सहित जरूरतमंद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फिशरीस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सरकारी सहायता प्रदान करने के लिए इन प्रमुख योजनाओं को जारी रखे हुए है। तटीय मछुआरों के लिए वैकल्पिक या अतिरिक्त आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए इन प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत आर्टिफिशियल रीफ्स, ओपेन सी केज कल्चर, सीवीड कल्टीवेशन, ओर्नामेंटल फिशरीस जैसी क्लाइमेट रेसीलिएंट गतिविधियों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

"तमिलनाडु में मात्स्यिकी क्षेत्र" के संबंध में 2 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए माननीय संसद सदस्यों डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन और श्री ससिकांत सैथिल द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 280 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण : विगत 3 वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं का वर्ष-वार योजना-वार विवरण

1. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

(रुपए लाख में)

क्रम सं	वर्ष	कुल परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत किया गया भारत सरकार का कुल शेयर	जारी किया गया भारत सरकार का कुल शेयर	उपयोग किया गया भारत सरकार का कुल शेयर
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
1.	2022-23	26	20779.81	6663.81	13807.38
2.	2023-24	23	4377.10	1585.57	3158.95
3.	2024-25	12	6991.05	1859.53	4239.77
कुल		61	32147.96	10108.91	21206.10

2. फिशरीस एंड एकाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (FIDF)

(रुपए लाख में)

क्रम सं	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना की कुल लागत	ब्याज अनुदान (इंटेरेस्ट सब वेनशन) के लिए स्वीकार्य परियोजना लागत	नाबार्ड से लोन स्वीकृति	
					स्वीकृत	वितरित
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1.	2022-23	32	23045	23045	5690	5175
2.	2023-24	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	2024-25	1	5920	2428	0.00	0.00
कुल		33	28965	25473	5690	5175

3. प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)

क्रम सं	वर्ष	स्वीकृत NFDप पंजीकरण	क्रेडिट के लिए प्राप्त आवेदन	एकाकल्चर इंश्योरेंस के आवेदन
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1.	2022-23	--	--	--
2.	2023-24	--	--	--
3.	2024-25	1,51,166	5197	391
कुल				